आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 21.04.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई।
- चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को स्वच्छ और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए यात्रा मार्ग पर त्वरित प्रतिक्रिया दल और मोबाइल खाद्य सुरक्षा वाहन तैनात।
- हरिद्वार में चारधाम यात्रा के मद्देनजर तीर्थात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा के लिए यात्रा सुरक्षा किट का वितरण शुरू।
- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं का परिणम 25 अप्रैल को घोषित किया जाएगा।

सहमति

उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों राज्यों ने यह निर्णय लिया है कि वे एक–दूसरे के अनुभवों, नवाचारों और कार्यप्रणालियों से सीखते हुए भविष्य में मिलकर काम करेंगे। एक रिपोर्ट–

खाद्य सुरक्षा/स्वच्छ भोजन

चारधाम यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को स्वच्छ और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग ने यात्रा मार्ग पर त्वरित प्रतिक्रिया दल और मोबाइल खाद्य सुरक्षा वाहन तैनात किए गए हैं। साथ ही होटल और ढाबा संचालकों के साथ संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

परीक्षा परिणाम

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 तथा सुधार परीक्षा 2025 का परिणाम 25 अप्रैल को पूर्वाह्न दस बजे घोषित करेगा। परिणाम परिषद सभागार में जारी किया जाएगा।

परिषद के अनुसार परीक्षार्थी अपना परिणाम परिषद की वेबसाइट पर देख सकेंगे।

इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा में 1 लाख 12 हजार 660 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों श्रेणियों के छात्र शामिल हैं। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 1 लाख 3 हजार 449 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।

दिशा बैठक

चम्पावत जिले में जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया।

बैठक में मंत्री ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने मडुवा और लाल धान जैसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–3 के तीसरे चरण के लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने और मनरेगा के तहत नई गाइडलाइन के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कृषि, बागवानी और पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत चयनित गांवों में कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा।

बुवाई

देशभर में ग्रीष्म ऋतु के लिए 17 अप्रैल तक 69 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसलों की बुवाई हो चुकी है। इनमें से 30 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान की बुवाई हुई है, जबकि दालों की बुवाई 15 दशमलव चार–सात लाख हेक्टेयर में हुई। श्री अन्न की बुवाई लगभग 13 दशमलव आठ–एक लाख हेक्टेयर में हुई है। तिलहन की बुवाई का क्षेत्र 9 दशमलव एक–चार लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है।

आपदा पुनर्वास

पिथौरागढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आपदा संवेदनशील गांव और तोकों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन ने धनराशि वितरित की है।

जिले की पाँच तहसीलों– धारचूला, मुनस्यारी, कनालिछिना, बंगापानी और पिथौरागढ़ से आपदा से संबंधित कुल 11 प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्राप्त हुए थे।

राज्य सरकार की भूमि पर इन परिवारों के सुरक्षित विस्थापन एवं व पुनर्वास के लिए प्रति परिवार को चार लाख पच्चीस हजार रुपए की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिसमें भवन निर्माण के लिए 4 लाख गौशाला निर्माण के लिए 15 हजार और घरेलू सामान के विस्थापन के लिए 10 हजार सम्मिलित हैं। कुल 75 परिवारों के लिए तीन करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि निर्गत की गई।

कुंभ मेला

कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अब धरातल पर तेजी से आकार ले रही हैं। मेला क्षेत्र में अवस्थापना से जुड़े लगभग तीन दर्जन महत्वपूर्ण कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं, जिन्हें आगामी अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मेलाधिकारी सोनिका खुद जमीनी स्तर पर निगरानी कर रही हैं।

इसी क्रम में कल मेलाधिकारी ने सीसीआर–2 भवन के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। मेलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी परियोजनाओं को 31 अक्टूबर तक पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।